# चीनी मिलों के लिए रियायतों की झड़ी

बिजनेस भास्कर • नई दिल्ली

**प्रधानमंत्री** मनमोहन सिंह द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को राहत देने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में 7,200 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना सबसे प्रमुख है। शुक्रवार को जीओएम की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने पत्रकारों से कहा कि बैठक में मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक और कदम उठाया गया है। एथनॉल की बिक्री के जरिये बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल में इसका मिश्रण पांच फीसदी से बढ़ाकर दस फीसदी करने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मिलों को 40 लाख टन रॉ शुगर के उत्पादन पर सब्सिडी दी जायेगी।

(विस्तृत समाचार पेज 9 पर)

बिजनेस भास्कर
7/12/13

बोझ ◆ उद्योग पर पिछले सीजन में खरीदे गन्ने का भी भुगतान बकाया

# चीनी मिलों को वित्तीय राहत के लिए रियायतों का पिटारा

## चीनी मिलों को ब्याज मुक्त कर्ज और रॉ शुगर पर सब्सिडी का तोहफा

बिजनेस भास्कर • नई दिल्ली

**रियायतें कैसी-कैसी**

- 7200 करोड़ रुपये के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा मिलों को
- चीनी मिलों की आय सुधारने के लिए पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण दोगुना
- 40 लाख टन रॉ शुगर के उत्पादन पर सब्सिडी देने की भी सिफारिश
- यूपी में मिलों की मदद के लिए 879 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पैकेज

**प्रधानमंत्री** मनमोहन सिंह द्वारा गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को राहत देने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में 7,200 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना सबसे प्रमुख है।

शुक्रवार को जीओएम की बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने पत्रकारों से कहा कि बैठक में मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक और कदम उठाया गया है। एथनॉल की बिक्री के जरिये बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल में इसका मिश्रण पांच फीसदी से बढ़ाकर दस फीसदी करने की भी मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा मिलों को 40 लाख टन रॉ शुगर के उत्पादन पर सब्सिडी दी जायेगी। शरद पवार ने कहा कि किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को बैंकों से 7,200 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। चीनी मिलों को मिलने वाले ऋण पर जो 12 प्रतिशत का ब्याज लगेगा, उसमें से सात प्रतिशत ब्याज का भुगतान शुगर डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ) से और पांच प्रतिशत का भुगतान केंद्र सरकार की तरफ से किया जायेगा। इस ऋण पर चीनी मिलों को दो साल तक कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक पेट्रोल में पांच प्रतिशत एथनॉल मिलाने की स्वीकृति थी, जिसे बढ़ाकर 10 फीसदी करने की मंत्री समूह ने सिफारिश की है। इसके चलते मिलों की एथनॉल बिक्री बढ़ने से आमदनी में सुधार होगा।

जीओएम की बैठक में कृषि मंत्री शरद पवार के अलावा वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र ) के वी थॉमस, नागर विमानन मंत्री अजीत सिंह और पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली उपस्थित थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बैठक में भाग लिया।

चीनी उद्योग के अनुसार मिलों को चीनी की बिक्री लागत से भी कम भाव पर करनी पड़ रही है, जिससे भारी घाटा हो रहा है। इस वजह से मिलें किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। उत्तर प्रदेश में पेराई सीजन 2012-13 का भी चीनी मिलों पर अभी करीब 2,300 रुपये बकाया बचा हुआ है। इसलिए उद्योग ने राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार से ब्याज मुक्त ऋण दिलाने की मांग की थी। चीनी के एक्स-फैक्ट्री दाम उत्तर प्रदेश में 2,900 से 3,050 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं जबकि मिलों को लागत करीब 3,400 से 3,600 रुपये प्रति क्विंटल की आती है।

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की निजी चीनी मिलों को 879 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था। साथ ही राज्य की चीनी मिलों को किसानों को दो किस्तों में भुगतान की भी अनुमति दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज में राज्य की चीनी मिलों को प्रवेश कर एवं क्रय कर के अलावा गन्ना समिति कमीशन से छूट मिली हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के एसएपी में उचित बढ़ोतरी नहीं होने और बकाया भुगतान को लेकर किसाने आंदोलन कर रहे हैं।